



"त्रिपल तलाक़ कानून : एक सामाजिक आवश्यकता"

प्रस्तावना

मार्थिन ल्युथर किंग ने "Stride Toward freedom" में कहा है की " आधुनिक एवम प्रगतिशील समाज में यदि कोई सामाजिक कुरीति किसी व्यक्ति को समानता एवम स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित करती है ! तो समय रहते समाज को इस कुरीति से मुक्त करा देना चाहिए यह कुरीति एक प्रगतिशील समाज से जड़ समाज में परिवर्तित कर देगी!

हमारे समाज में एक सोच बहुत ज्यादा प्रभावशाली है और वो है बिना सोचे - समझे किसी प्रथा को जन्म दे देना! सम्पूर्ण ज्ञान न होते हुए भी लोग परंपरा को मान देने लगते हैं फिर चाहे वे किसी अन्य के लिए दुखदायी ही क्यों न हो !कुछ इसी प्रकार की सोच का परिणाम है वर्तमान में प्रचलित " तिन तलाक़" की परंपरा ने न जाने कितनी ही महीलाओ के जीवन को नरक बना दिया है और न जाने कितने अनगिनत घर - परिवारों को नष्ट किया! आज धर्म और परंपरा के नाम पर सुधार एवम आवश्यकता है!

अध्ययन के उद्देश्य

- त्रिपल तलाक़ की ऐतिहासिक एवं वर्तमान परिस्थिति का परिचय करना.
- भारतीय मुस्लिम महिला की त्रिपल तलाक़ कुप्रथा के विरोध के कारणों को समझना
- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से समाज में आने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन को समझना .

अनुसन्धान अध्ययन का महत्व

- त्रिपल तलाक़ भारतीय मुस्लिम महिलाओ के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या है, ये 9 करोड़ महिला के साथ उसका ताल्लुक है.
- ये कुप्रथा भारतीय संविधान : समानता , स्वतंत्रता, एवं मानवीय अधिकारों के विरुद्ध है , इसी लिए उसे कानून बनना आवश्यक पूर्ण है

मुसलमानों में विवाह विच्छेद :

मुस्लिम विवाह एक संविदा अथवा समझौता है, अतही उसे तोडना अर्थात विवाह विच्छेद करना न्याय संगत माना गया है! मुसलमानों में पति - पत्नी का सम्बन्ध सामाजिक अथवा आर्थिक रूप से देखा जाता है . अटूट जन्म - जन्मान्तर का नाता नही माना जाता !

मुसलमानों में विवाह विच्छेद एक आम बात है यह प्रक्रिया सरल मुस्लिम समाज में है, उतनी अन्य समाज में देखने को नही मिलती! यदपि व्यावहारिक जीवन में मुस्लिम विवाहों में भी स्थिरता पाई जाती है, यथापि विवाह- विच्छेद या तलाक़ किसी भी समाज की अपेक्षा अधिक खुली छुट है! इस क्षेत्र मे भी इस्लामी कानून पुरुषो के पक्ष में जुका हुआ है! उदाहरण : पुरुष तो बिना कोई कारण बताए ही केवल तलाक़ का उच्चारण मात्र करने से सम्बन्ध विच्छेद कर शकता है, जबकि स्त्री ऐसा तब तक नही कर शकती जब तक की वह पुरुष को दोषी प्रमाणित न करे! मुस्लिम समाज में बिना अदालत के सामाजिक रूप से विवाह - विच्छेद करना अति सरल है और न्यायिक रूप से भी इसमे कोई विशेष अडचन नही है!

एस प्रकार मुस्लिम समाज में तलाक़ के दो प्रकार से किया जा सकता है - १} बिना अदालत के और २ } अदालत द्वारा] अथवा प्रथागत रूप में तथा क़ानूनी ढंग से! तथा क़ानूनी ढंग से अग्रिम पंक्तियों में हम तलाक़ के प्रथागत स्वरूप 1] customary form 2] judicial form दोनों की अदालती स्वरूप दोनों की विवेचना करेंगे!

तलाक़ का प्रथागत स्वरूप : Customary form of Divorce

मुस्लिम समाजमें तलाक़ का प्रथागत स्वरूप यही अधिकांशतः प्रचलित है. तलाक़ प्रायः बिना अदालत की सहायता के होते हैं और इस दृष्टि से पुरुष को बहुत ही व्यापक अधिकार मिले हुई हैं! तलाक़ के प्रथागत प्रकार

१. तलाक़

1. तलाके अहसन : Talak e ahashan

2. तलाके हसन : Talak hasan

3. तलाके बिदत : तलाक़ - उल - बिदत / त्रिपल तलाक़

२. इला . ३ बिहार ४. खुल्ला ५. मुबारत ६. लियांन ७ . तलाक़ तफ़बिज .

उपरोक्त प्रकार के तलाक़ बिना अदालत के प्रथागत रूप में किया जा सकते हैं तथा इनका प्रयोग केवल पति ही कर सकता है ! पत्निया केवल पति की सहमती से ही विवाह विच्छेद कर सकती है! तलाक़ के इन स्वरूप या प्रकारों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है!

अलिखित या मौखिक तलाक़ के तिन प्रकार होता है.

१.) तलाके अहसन :

इसमें पत्नी के "तुहर" [मासिक धर्म] के समय पति एक बार तलाक़ की घोषणा कर देता है और इदत की अवधि तक सहवास नहीं करता है और इदत की अवधि समाप्त होती है, तो विवाह का नाता भी टूट जाता है! इदत के समय पत्नी असुराल में रहती है , और इदत का समय ३ महीने १० दिन है. इसमें समझौता के अवकाश ज्यादा है.

२) तलाके -हसन :

इसमें तीनों "तुहरो " मासिक धर्म के समय तलाक़ की घोषणा दोहरानी पडती है. तिन तुहरो के बिच समय में पति -पत्नी सहवास नहीं करते! तीसरे तुहरे अर्थात मासिक धर्म पर तलाक़ की घोषणा दोहराने के बाद तलाक़ पूरा हो जाता है.

३) तलाके - विदाई या तलाक़ उल - बिदत / त्रिपल तलाक़ क्या है?

तलाक़ का यह सबसे आसन तरीका है! इसमें किसी तुहर के समय पति एक ही बार स्पष्ट रूप से तलाक़ एकदम हो जाता है ! घोषणा के समय पत्नी या गवाह की उपस्थिति आवश्यक नहीं है!

कभी कभी यह भी होता है की एक ही तुहर के समय थोड़े थोड़े समयांतर से तलाक़ की घोषणा तिन बार की जाती है और तलाक़ पूरा माना जाता है!

उलेखनीय है की तुहर के समय ही तलाक़ की घोषणा का नियम इसीलिए लिखा गया है ताकि यह पता चल जाए की तलाक़ के समय स्त्री गर्भवती तो नहीं थी!

तिन तलाक़ को कुरान में इजरत मोहहमदजि ने नापाक एवं गुनहा माना है, ओमयाद के राजाओ ने ६४० में अरब की स्थापना की और तिन तलाक़ और बहुपत्नी प्रथा को बढ़ावा दिया था.

- यहा तलाके हसन और तलाक़ ऐ उल बिदत में मुख्य अंतर को समझ लेना चाहिए की जहा तलाक़ हसन तोडा जा सकता है अर्थात विवाह फिर से चालू रखा जा सकता है वहा तलाक़ ऐ विदाई को समाप्त नहीं किया जा सकता अर्थात एक बार तलाक़ हो गया तो उसे लौटाया नहीं जा सकता! तलाक़ ऐ अहसन और तलाक़ ऐ हसन में मुख्य अंतर यह है की जहा पहले तलाक़ इदत का समय पूर्ण होने के दूसरा तलाक़ तीसरी घोषणा के बाद पूर्ण माना जाता है!

- **मुस्लिम वस्ती विश्लेषण :**

भारत में १४.२ % मुस्लिम वस्ती है, १७२ मिलियन लोग इस्लाम धर्म के पाए गए हैं जिसमे भारतीय मुस्लिम महिलाओ की आबादी 9 करोड़ है . भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुस्लिम वस्ती वाला देश है.

- **त्रिपल तलाक़ विरोद्ध के कारण**

१. पत्नी की सहमती या पूर्व जानकारी के बिना

२. पति का तानाशाही रुख

३. समजौता का विकल्प नहीं

४. विडियो कॉल , मेसेज, इ-मेइल, आदी से तलाक

५. पकिस्तान, तुर्की, सहित २२ मुस्लिम देशो में त्रिपल तलाक़ प्रतिबंधित है.

६. तलाक के बाद सामाजिक, आर्थिक, स्थिति दयनीय कारण भरण-पोषण प्रावधान नहीं.

७. अनैतिक, अलोकतांत्रिक एवम महिला सशक्तिकरण के प्रयास के विरोद्ध में है .

९. मिस्र, ट्युनिसिया, इराक, बांग्लादेश, ओमान, कतर, तुर्की इन मुस्लीम देशो में बिना अदालत के तलाक नहीं हो सकते .

- **त्रिपल तलाक के मामले विभिन्न पक्ष**

[१]. मुस्लिम महिलाओ का पक्ष:

भारतीय मुस्लिम महिलाओ के पर सर्वे से पता चला की 9२% मुस्लिम महिलाए त्रिपल तलाक और बहुपत्नीत्व के विद्रोह में समर्थन दिया, सर्वे से पता चला की उन्हें साथ जबरजस्ती, आकरण, कभी कभी दहेज के कारण भी, बेटी के जन्म जैसे अन्य सामाजिक - आर्थिक समस्याओ के कारण तलाक बन सकता है .

मेरा हक फाउंडेशन नेतृत्व {बरेली } में विरोद्ध हुआ है.

[२]. All India Muslim personal Law bord के मुद्दे :

उनके मुताबित संविधान अनुच्छेद २५-२९ अप्लसंख्यको के धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का रक्षण में हस्तक्षेप नहीं करे.

मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिकार १९३९ औरतो को भी तलाक का हक है.

तिन तलाक पर प्रतिबद्ध शरीयत कानुन से छेड़छाड़ अतः उन्हें मंजूर नहो है.

[३] सरकार का पक्ष :

भारत धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतान्त्रिक देश इस तरह की कुरीतियों संवैधानिक मूल्यों एवं संस्कारो के विपरीत है , महिला के सम्मान एवं लैंगिक समानता के विरुद्ध है , धार्मिक कानुन की समानता {अ.१४ } एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार पर वरीयता नहीं दी जा सकती {a-२१} .

- **कानुन का अर्थ :**

कानुन मनुष्य की जरूरियात का सर्जन है, कानुन शासन का हेतु जनकल्याण है

सर जॉहन सामंड :कानुन ऐसे नियमो का समूह है की जिसे राज्य द्वारा न्याय का विभाजन को स्वीकृत अमल करने के लिए हो .

जस्टीनयन: कानून यानि योग्य एवं अयोग्य का मापदंड .

प्रो.एच. एल. हार्ट: कानून नियमों की पद्धति है.

यह कुप्रथा दूर करना सिर्फ धर्म से, या मजहब से लड़ाई नहीं है , है ये उन 9 करोड़ भारतीय मुस्लिम महिलाओं के सम्मान, समानता , जेंडर इक्विटी और जेंडर न्याय की मांग है . जो हमारे भारत के संविधान में और मानव हक में प्रदान की गई है! सर्वोच्च अदालत की पांच जजों की संवैधानिक पीठ मुस्लिम समाज में प्रचलित 'तिन तलाक़', 'निकाह हत्ताला', और 'बहु विवाह', की प्रथा को लेकर दायरा याचिका पर सुनवाई करके फैसला २२ अगस्त २०१७ में किया की :

- त्रिपल तलाक़ क़ानूनी रूप से अवैध एवम गैर संवैधानिक है.
- त्रिपल तलाक़ देने वाले को तिन साल की सजा और जुर्माना
- त्रिपल तलाक़ की पीड़ित और उसके बच्चे को भत्ता मिलेगा
- नाबालिक बच्चेका जिम्मा अपने माँ के पास होगा
- यह ठराव जम्मू- कश्मीर के आलावा भारत भर में लागू होगा .
- तलाक़ बोलके, लिखके या इलेक्ट्रिक माध्यम से नहीं दे सकते ,उसे क़ानूनी नोटिस के माध्यम से ही भेजा जाये.

यह फैसला उन ४० साल से लड़ रही साहबानों जो तिन तलाक़ से अपने ७ बच्चे के साथ घर से बेघर की गई थीं उन जैसी हजारों महिलाओं की जीत बन गई है . जिन्होंने ये कुर्रति के खिलाफ आवाज उठाई. यहा ये बताना जरूरी है की इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र ग्रन्थ कुरान में तिन तलाक़ को गुन्हा माना गया है ! लेकिन पुरुषवादी सोच के चलते मुस्लिम समाज में यह कुरीति प्रचलित है!

लोकसभा में the Muslim women (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स ऑफ़ मर्जिज बिल २०१७) पास हो गया है, पर अभी तक राज्यसभा में बिल नहीं पास हुआ है. यह तभी कानून बनेगा जब राज्यसभा की बहुमति और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे! महिलाओं के समान हक़ का महत्व हमें देश को, नई पीढ़ी को समझाना पड़ेगा : हमारे देश की आधी आबादी को हम पीछे रखके कभी भी प्रगति की ओर जा नहीं सकते! हमें ऐसे तीखे सवाल उठाना पड़ेंगे और मानवीय हक़ के लिए आगे आना चाहिए !

समापन

इस तरह त्रिपल तलाक़ भारतीय मुस्लिम महिला की योग्य मांग है, सुप्रीम कोर्ट ने भी त्रिपल तलाक़ को अवैध माना है, ये कुप्रथा महिला सशक्तिकरण एवं मानव अधिकारों के खिलाफ है. पर राजनिक स्वार्थ, वोटबैंक, परंपरागत धर्मगुरु, एवं कट्टरवादी धार्मिक नेता के विरोध से अभी भी ये कानून नहीं बन सका है, हमें धर्म, राजकारण, निजी स्वार्थ को नजर अंदाज करके भारतीय मुस्लिम महिला के स्वाभिमान, सुरक्षा एवं उनकी गरिमा का ख्याल करके देशहित में कानून बनना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है.

संदर्भ

- I. महिला एवं कानून : _चेतना मेहता _इफ़ेसिएन्ट आफ़सेट प्रेस
- II. विवाह का समाजशास्त्र _ डॉ. एम्. एन. लवानिया _ रिसर्च पब्लिकेशन
- III. दारे कुरानी, भाग ४, पेज नं. २० दुर्रे मंसूर, भाग २ पेज नं. ३३३
- IV. न्याय शास्त्र : बोर्देन हार्डमन १९७४ , भाग १०
- V. भारतीय बंधारण : मुलभुत अधिकार

- VI. कुशन सूय २. सूय ऐ तलाक आयात [२२८- २३४] [१ -७]
- VII. <http://www.ishanllb.com>
- VIII. ummat - e- nabi foundation
- IX. Amalytical studies of the Rule of law in Constitution of india, in the context of fundamental rights : dhiren chhotal : phd thesis.
- X. www.indiacensus.com

Vyas Radhika Maheshchandra
Maharaja Krishnkumarsinhji Bhavnagar University

Copyright © 2012 – 2018 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat